

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला-अजमेर)

गोठारी अधिकारी - डॉ० आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या 7/2012

उनवान

श्रीमती अमराव पुत्री स्वर्गीय श्री मोती जी पत्नी श्री जोरा जी आयु 65 साल जाति ठाकर (चीता) हाल निवासी ग्राम काशीपुरा वाया खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर

बनाम

1. भेंवरी पत्नी श्री बन्ना जी पुत्री स्व० श्री कालू जी आयु 55 साल निवासी ग्राम सेदरिया पर्वतपुरा बाईपास अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम

आदेश

दिनांक :- 23.12.2019

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष वकिल उपस्थित । जिन्हे राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर सुना गया । अपीलान्त अभिभाषक ने दौरान बहस मे निवेदन किया गया कि अपीलार्थी 65 वर्षीय वृद्ध महिला है जो वर्तमान में अपने परित के साथ ग्राम काशीपुरा वाया खरवा तहसील मसूदा में निवास कर रही है। प्रार्थीया के पिता श्री माती पुत्र श्री दूला जी का स्वर्गवास हो चुका है जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद ग्राम मुहामी तहसील अजमेर में खाता नंबर 265 खसरा नम्बर 1663, 1766, 1884, 1889 कुल रकबा पाँच बीघा उन्नसी बिस्वा छोडी है । प्रार्थीया/अपीलार्थीया के पिता श्री माती वल्द दूला अपनी मृत्यु से पूर्व तक उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर तन्हा रूप से मालिक व काबिज रहे है जो उनकी मृत्यु से पूर्व तक राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीया के पिता स्वर्गीय श्री मोती वल्द दूला के नाम अंकन रही । अपीलार्थीया के पिता श्री मोती के देहान्त के बाद अपीलार्थीया के अलावा अपीलार्थीया का एक अन्य भाई कालू स्वर्गीय श्री माती जी के विधिक वारिसान रहे एवं अपीलार्थीया की माता श्रीमती राजी व अपीलार्थीया के पिता श्री मोती जी का देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलार्थीया व उसका भाई कालू बराबर बराबर सम्मितलित रूप से मालिक व काबिज हुए। अपीलार्थीया के पिता के देहान्त के बाद अपीलार्थीया के भाई स्वर्गीय श्री कालू ने तथ्यों को छुपाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष गलत तथ्य प्रकट करते हुए

अपीलार्थीया के पिता श्री मोती द्वारा छोड़ी गई उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में अकेले के नाम नामान्तरित करवा लिया जो कि राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 3 दिनांक 22.6.1995 को अपीलार्थीया के स्वर्गीय भाई श्री कालू पुत्र श्री मोतीजी के नाम नामान्तरित हुई जब कि अपीलार्थीया के पिता श्री मोतीजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने किसी भी विधिक वारिसान के पक्ष में उक्त कृषि भूमि बाबत किसी भी प्रकार का कोई वरीयतनामा या अन्य कोई दरसावेज निष्पादित नहीं किया ना ही स्वर्गीय श्री मोतीजी ने अपने जीवनकाल में अपने किसी विधिक वारिसान के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का किसी प्रकार से विभाजन ही किया इसके बावजूद भी अपीलार्थीया के स्वर्गीय भाई श्री कालू ने स्वर्गीय श्री मोती जी का अपने आपको अकेला विधिक वारिसान प्रदर्शित करते हुए उक्त कृषि भूमि का अपने नाम नामान्तरण करवा लिया जबकि अपीलार्थीया स्वर्गीय श्री मोती जी पुत्र श्री दूला जी के जाईन्दा संतान होकर उनकी विधिक वारिसान होने की हैसियत से उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से की सहहिस्सेदार है। अपीलार्थीया के भाई का देहान्त आज से करीब चार वर्ष पूर्व हो चुका है एवं श्री कालू की पत्नी श्रीमती शकीना का देहान्त पांच वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 1 जो कि अपीलार्थीया के भाई श्री कालू की एक मात्र संतान है ने अपने पिता श्री कालू के देहान्त के बाद राजस्व रेकार्ड में उक्त कृषि भूमि अपने नाम नामान्तरित करवा ली जो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 को नामान्तरित हुई। अपीलार्थीया के पिता व माता के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता श्री कालू ने उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीया का 1/2 हिस्सा हडप करने व अपने आपको एक मात्र स्वर्गीय मोतीजी का विधिक वारिस बताकर राजस्व रेकार्ड में उक्त कृषि को अपने नामा नामान्तरित करवा ली एवं श्री कालू के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने आपको श्री कालू की विधि वारिस बताकर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम नामान्तरित करवा ली जबकि उक्त कृषि भूमि में आज भी अपीलार्थीया का स्वर्गीय श्री मोती पुत्र दूला जी की विधिक वारिस व जाईन्दा संतान होने की हैसियत से 1/2 हिस्सा कायम है एवं आज भी अपीलार्थीया अपने पिता श्री मोतीजी के देहान्त के बाद से ही उक्त वर्णित कृषि भूमि में काबिज रहकर काशत करती आ रही है। इस प्रकार अपीलार्थीया के स्वर्गीय भाई श्री कालू पुत्र श्री मोती द्वारा अपीलार्थीया के पिता श्री मोती पुत्र श्री दूला ही के देहान्त के बाद तथ्यों को छुपाकर अपने आपको स्वर्गीय मोती का एक मात्र विधिक वारिस बताते हुए एवं अपीलार्थीया के भाई श्री कालू के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छुपाकर राजस्व रेकार्ड में अपील में वर्णित चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमि से संबंधित अपीलार्थीया के भाई श्री कालू के हक में हुए नामान्तरण संख्या 3 दिनांक 22.6.1995 एवं श्री कालू के देहान्त के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि के क्रम में करवाया गया नामान्तरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलार्थीया को विगत दिनों यह जानकारी हुई कि



अधिकारी

संख्या 1 उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीया को 1/2 हिस्सा दिये बिना ही कृषि भूमि पर अपने अपीलार्थीया को 1/2 हिस्सा दिये बिना ही उक्त कृषि भूमि पर अपने आपको अकेले मालिक बताकर उक्त कृषि भूमि का बेचान करने पर आमादा है जिस पर अपीलार्थीया द्वारा उक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी) की नकल प्राप्त की गई जो अपीलार्थीया को दिनांक 7.5.2012 को प्राप्त होने पर उसका अवलोकन किये जाने के बाद अपीलार्थीया को तथ्यों को छुपाकर व गलत आधार पर स्वर्गीय श्री कालू पुत्र मोती एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा करवाये गये नामान्तकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से सम्पर्क कर उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करने एवं राजस्व रेकार्ड में गलत आधारों पर तथ्यों को छुपाकर करवाये गये नामान्तकरण को निरस्त करवाने का अनुरोध किया। अतः अपीलान्त अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपील की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकार्ड में स्वर्गीय श्री कालू पुत्र मोती एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 2.6.1995 एवं नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 को निरस्त करने के आदेश व शून्य घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट एक की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 73 के स्थान पर 3 दिनांक 2.6.1995 एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलाधीन पक्षकार ही नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलानार्थीया के द्वारा अपीलाधानी नामान्तकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के संदर्भ में माननीय न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने के संदर्भ में अनुमति लिया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलार्थीया के द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के संदर्भ में माननीय न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त ही नहीं की गई इस कारण अपीलार्थीया की अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीया के द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 107/2012 अनतर्गत धारा 88 एवं राज्यस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया तथा इसी वाद में अपीलाधीन नामान्तकरण को भी चुनौती दी गई है उक्त स्थिति में अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। तथा अपीलार्थीया के द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में रेग्युलर वाद प्रस्तुत किया गया। जो न्यायालय सहायक कलक्टर (मु) अजमेर द्वारा दिनांक 19.11.2012 को अदम हाजरी में खारिज किया गया। अतः प्राथमिक आपत्ति आवेदन पत्र मय खर्चे अपील निरस्त किया जावे।

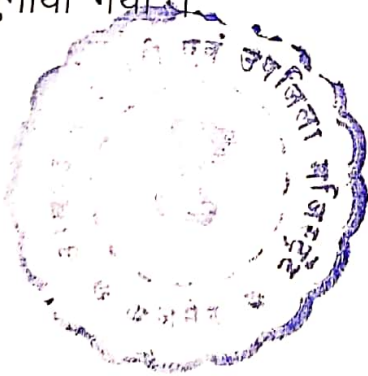


वकील अपीलान्त द्वारा आवेदन पत्र प्राथमिक आपत्ति की प्रति दिनांक 28.9.2012 को प्राप्त किये जाने के बाद आज दिनांक तक उक्त प्राथमिक आपत्ति का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण संख्या 3 दिनांक 2.6.95 एवं नामान्तकरण संख्या 1146 दिनांक 5.8.2011 दो भिन्न-भिन्न नामान्तकरण की एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि दो नामान्तकरण अथवा दो आदेशों के एक अपील नहीं हो सकती इस संबंध में 2013 (1) आरआरटी 659 न्यायिक दृष्टांत सुसंगत है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दो आदेश की एक अपील संधारण योग्य नहीं है, एवं अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है । रेस्पोंडेंट आपत्तिकर्ता की विधिक आपत्ति न्यायोचित व उचित है। अपील अपीलान्त की अपील इसी कानूनी विन्दु पर खारिज योग्य है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही अपील प्रस्तुति की स्वीकृति ली गई इस कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत भी अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः रेस्पोंडेंट आपत्तिकर्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2012 स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्त अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्त खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।



डॉ० आर्तिको शुक्ला (आई.ए.एस.)
उप-उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

